IJCRT.ORG ISSN : 2320-2882

INTERNATIONAL JOURNAL OF CREATIVE RESEARCH THOUGHTS (IJCRT)

An International Open Access, Peer-reviewed, Refereed Journal

नरेन्द्र मोदी कार्यकाल में भारत–नेपाल संबंध

राजेश कुमार

पी०एच०डी०, शोधार्थी
राजनीति विज्ञान विभाग
कु० मायावती राजकीय महिला स्नातकोत्तर
महाविद्यालय, बादलपुर, गौतमबुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश।

डॉ0 सीमा देवी

शोध निर्देशिका
राजनीति विज्ञान विभाग
कु० मायावती राजकीय महिला स्नातकोत्तर
महाविद्यालय, बादलपुर, गौतमबुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश।
चौ० चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ, उत्तर प्रदेश।

भारत–नेपाल, दोनों ही देशों में पड़ोसी के तौर पर घनिष्ट संबंध हैं। इनका संबंध सहयोग और मैत्री के रूप में व्याख्यायित किया जाता है। निसंदेह रूप से दोनों देशों के बीच लोगों का बेरोक–टोक आवागमन दोनों ही देशों के लिए महत्वपूर्ण स्थान रखता है। 1950 में भारत नेपाल संधि दोनों देशों के बीच संबंधों की मजबूत आधारशिला है। यह संधि कुछ मायनों में नेपाली नागरिकों को भारतीय नागरिकों के समान सुविधाएं प्रदान करती है।

नेपाल, भूटान की तरह भारत का दूसरा सबसे पुराना, सबसे घनिष्ठ और सबसे विश्वासपात्र मित्र हैं। भारत और नेपाल खुली सीमा संबंधों के साथ अपने संबंधों के विशेष गुणों को साझा करते हैं। यह दोनों देशों के साथ गहराई से जुड़ें हुए संबंधों को स्थापित करता हैं जिसको बड़े पैमाने पर दोनों देशों में सीमा पार स्वतंत्र गति के रूप में स्वीकार किया है और इसका दोनों ही देशों के लोगों के द्वारा आनंद लिया जाता है। यह किसी भी देश के साथ भारत के संबंधों के मामले में एक अपवाद मामला है। शांति और मित्रता का भारत–नेपाल संधि, जिसको दोनों देशों के बीच 1950 में हस्ताक्षर किया गया, दोनों देशों के साथ स्वस्थ संबंधों की नींव रहा है। इस संधि के अन्तर्गत नेपाली नागरिक भारतीय जमीं पर कई अवसरों पर आनंद लेते हैं जो किसी दूसरे देश के नागरिकों के लिए नहीं है। भारत–नेपाल संबंधों का महत्व इस बात से भी समझा जा सकता है कि भारतीय सेना के पास गोरखा रेजीमेंट ह इसके सभी सैनिक नेपाल के गोरखा समुदाय से सम्बन्ध रखते हैं। इससे हटकर दोनों देश संस्कृति, अर्थव्यवस्था, रक्षा, स्वास्थ्य और हर क्षेत्र पर बहुत से समझौते रखते हैं जो उनके संबंधों को मजबूत करता हैं। उदाहरण के तौर पर दोनों देश सीमा वाले क्षेत्रों में काम करने के लिए शक्ति क्षेत्र में आधारभूत संरचना को साझा करते है। दोनों देशों के बीच विद्युत विनिमय करने के लिए एक समझौता 1971 में हस्ताक्षर किया गया जो विद्युत क्षेत्र में आधारभूत संरचना को साझा करने के लिए निर्देश तैयार करता है। उसी स्वरूप पर ''विद्युत शक्ति व्यापार, सीमा पार प्रसारण अंतरसंपर्क और ग्रीड सम्पर्क'' पर एक नए समझौता 21 अक्टूबर 2014 को हस्ताक्षर किया गया। इस समझौता को दोनों देशों की आवश्यकताओं को

पूरा करने के लिए और नेपाल को विद्युत क्षेत्र में स्वावलंबी बनाने के लिए तैयार किया गया हैं जो भविष्य में भारत को लाभ पहुंचायेगा।

इन दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों में दूसरे महत्वपूर्ण क्षेत्र शिक्षा और संस्कृति क्षेत्र हैं। वर्तमान में भारत नेपाली नागरिकों को 3000 छात्रवृत्ति प्रदान करता हैं जो उनको भारत में उच्च शिक्षा प्राप्त करने में लाभ पहुंचाएगा। भारत और नेपाल की सरकार अपने बीच अच्छा संबंध बनाने के लिए लोगों तक सम्पर्क को बढ़ावा देने पर जोर देती हैं। अपने सांस्कृतिक सम्बंध को तेज करने के लिए दोनों देश कला और संस्कृति के कई कार्यक्रम का आयोजन करते हैं और संगोष्ठी ओर विचार गोष्ठी कराते हैं। यह भी नोट करना आवश्यक हैं कि कई समझौते भारत और नेपाल के बीच हस्ताक्षरित हो चुके हैं। दूसरा महत्वपूर्ण निर्णय नेपाल में भारतीय संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए दोनों देशों के बीच लिया गया। इस समझौते के अंतर्गत स्वामी विवेकानन्द सेंटर फॉर इंडियन कल्चर के रूप में जाना जाने वाला एक्सिलेंस फोर कल्चर का एक केंद्र को भी नेपाल में भारतीय संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए 2007 में स्थापित किया गया। भारत हमेशा नेपाल की विकास रूपी आवश्यकताओं को पूरा करने में और नेपाल की आर्थिक वृद्धि को तेज करने में उसका बहुत सहयोगी और सहायक रहा है। भारत ने शिक्षा, स्वास्थ्य, रक्षा, जल संसाधन, सड़क और रेल मार्ग इत्यादि के क्षेत्र में कई विकास रूपी परियोजना को लागू करने में आर्थिक रूप से और तकनीकी रूप से नेपाल की सहायता की है। भारत के द्वारा प्रदान की हुयी यह सहायता नेपाल में लोगों के जीवन को बदलने में बहुत प्रमुख भूमिका निभा चुकी है।

दोनों देश उच्च स्तरीय मुलाकातों को बनाऐं रखते हैं जो उनके संबंधों को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मोदी सरकार 2014 से नेपाल के साथ मित्रवत और स्वस्थ सम्बंध बनाए रखें हुए हैं जो इस तथ्य को दर्शाता है कि पीएम मोदी तीन बार से नेपाल की यात्रा कर चुके हैं। नेपाल की उनकी यात्रा दोनों देशों के बीच सम्बंध के नये रूप को स्थापित कर चुकी है।

2014 में पूर्ण बहुमत प्राप्त करने के बाद नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने के अवसर पर सार्क देशों के नेताओं को आमंत्रित किया था। यह न केवल एक अभूतपूर्व कदम था, बल्कि दक्षिण एशिया के प्रति उनके नजरिये को भी यह दर्शाता है। उन्होंने महसुस किया कि क्षेत्रीय शक्ति बनने के लिए भारत के चारों और पडोसियों के साथ दोस्ताना संबंध बनाने होंगे।

प्रधानमन्त्री की नेपाल यात्राः पड़ोसी देश के साथ नए युग की शरुआत

भारत के प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी 3–4 अगस्त, 2014 को अपनी दो–दिवसीय यात्रा पर नेपाल गए। अपने पड़ोसी देशों से बेहतर सम्बन्धों के निर्माण को अपनी विदेश नीति की प्राथमिकता में रखने वाले मोदी 17 वर्षों के बाद नेपाल की यात्रा पर जाने वाले पहले भारतीय प्रधानमन्त्री बने। मोदी के साथ करीब 100 लोगों का शिष्टमंडल भी नेपाल गया। नेपाल में बढ़ रही चीन की रुचि को देखते हुए भी इस यात्रा का विशेष महत्त्व है।

मोदी ने अपनी यात्रा के दौरान विपक्ष के नेता प्रचंड और यू.एम.एल., मधेशी मोर्चा सहित कई राजनीतिक दलों के नेताओं से मुलाकात की। गौरतलब है कि मोदी के इस दौरे से पहले वर्ष 1997 में तत्कालीन प्रधानमन्त्री इन्द्रकुमार गुजराल ने नेपाल की यात्रा की थी। नेपाल जाने वाले आखिरी प्रधानमन्त्री अटल बिहारी वाजपेयी थे, जो सार्क सम्मेलन में भाग लेने के लिए वर्ष 2002 में नेपाल गए थे। इस यात्रा में खास यह रहा कि नेपाली प्रधानमन्त्री ने प्रोटोकॉल तोड़ा, नेपाली संसद रविवार को खुली, भारतीय प्रधानमन्त्री ने नेपाल की संसद को सम्बोधित किया।

मोदी का प्रोटोकॉल तोड़ किया जोरदार स्वागत

नेपाल के प्रधानमन्त्री सुशील कुमार कोइराला ने 3 अगस्त, 2014 को प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी की आगवानी करने के लिए राजनयिक प्रोटोकॉल तोड़ा। कोइराला स्वंय काठमांडू स्थित त्रिभुवन हवाई अड्डे पर गए तथा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी का स्वागत किया।

ऐसा पहली बार हुआ जब कोई शासनाध्यक्ष दूसरे शासनाध्यक्ष के स्वागत के लिए हवाई अड्डे तक पहुँचा। इसके साथ ही प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी को हवाई अड्डे पर 21 तोपों की सलामी भी दी गई। यही नहीं उनके स्वागत–सत्कार का अन्दाजा इसी से लगाया जा सकता है कि नेपाल ने मोदी के आगमन पर दो दिनों का राष्ट्रीय अवकाश तक घोषित कर दिया।

नेपाल की संविधान सभा को किया सम्बोधित

प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी ने 3 अगस्त, 2014 को नेपाल की संविधान सभा (नेपाली संसद) में ऐतिहासिक भाषण दिया। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी ने 'नेपाली भाषा' में शुरू किए गए अपने भाषण से सदन में बैठे 500 सांसदों का दिल जीत लिया।

इन समझौतों पर बनी सहमति

1. नेपाल में आयोडीन की कमी वाली बीमारियों से निपटने को आयोडीन युक्त नमक की आपूर्ति करने के लिए भारत 6.90 करोड़ नेपाली रुपए की अनुदान सहायता देगा।
2. दोनों देशों के सरकारी टीवी (नेपाल टेलीविजन और दूरदर्शन) के बीच सहयोग।
3. पंचेश्वर बहुउद्देशीय बाँध परियोजना की शर्तों में संशोधन के साथ कार्य प्रारम्भ करने पर सहमति।

मोदी ने की पशुपतिनाथ मन्दिर में विशेष पूजा

सावन के आखिरी सोमवार पर प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी ने काठमाण्डू स्थित पशुपतिनाथ मन्दिर में विशेष पूजा की। मन्दिर में नेपाल वेद विद्याश्रम के 108 पुजारियों ने प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी के स्वागत में मन्त्र पढ़े। जबकि रुदाभिषेक के लिए 150 पुजारी मौजूद थे। मोदी ने 45 मिनट पूजा की। मोदी ने मन्दिर में 2500 किग्रा चन्दन की लकड़ी भी दान में दी। पूजा, मुख्य पुजारी दक्षिण भारतीय मूल के गणेश भट्ट के नेतृत्व में हुई। भारत सरकार ने पशुपतिनाथ मन्दिर के संरक्षण के लिए 25 करोड़ का पैकेज दिया है। साथ ही मन्दिर परिसर में 400 बिस्तरों की धर्मशाला बनाने का भी ऐलान किया। पशुपतिनाथ मन्दिर नेपाल की राजधानी काठमांडू से 3 किमी. उत्तर–पश्चिम में देवपाटन गाँव में बागमती नदी के तट पर स्थित है।

पंचेश्वर बाँध परियोजना होगी शुरू

वर्षों से काली नदी पर पंचेश्वर बाँध परियोजना लम्बित है। दोनों देशों के मध्य हुए समझौते के अनुसार, वर्ष 1996 में हस्ताक्षरित 5600 मेगावाट की इस परियोजना के लिए, पंचेश्वर विकास की इस परियोजना के लिए पंचेश्वर विकास प्राधिकरण का गठन किया जाएगा और एक वर्ष के अन्दर परियोजना रिपोर्ट को अन्तिम रूप दिया जाएगा। समझौते के अनुसार, दोनों देश पंचेश्वर प्राधिकरण विनियम की घोषणा के जरिए पंचेश्वर विकास प्राधिकरण से जुड़े कार्यों को आगे बढ़ाने पर सहमत हो गए। यह परियोजना महाकाली नदी पर एकीकृत सन्धि के तहत आती है। यह परियोजना रुपये 30000 करोड़ की लागत से बनेगी। इस परियोजना पर 1315 मी. ऊँचाई, का बाँध बनेगा।

नेपाल में भूकंप

25 अप्रैल 2015 को नेपाल में 7.8 रेक्टर स्केल का भूकंप आया था। उस दौरान भारत सरकार ने राष्ट्रीय आपदा राहत बल और विशेष वायुयान भेजा था, जिसमें राहत सामग्री थी। महत्वपूर्ण बात यह है कि भूकंप के छह घंटे के भीतर यह राहत सामग्री वहां पहुंच चुकी थी। इसमें एन.डी.आर.एफ की 16 टीमें, 39 आर.ए.एफ एयरक्राफ्ट और कई टन राहत सामग्री थी। यह राहत सहायता करीब 67 मिलियन अमेरिकी डालर के बराबर थी।

नेपाल में भारतीय निवेश

31 मई, 2017 तक भारत से नेपाल में एफ.डी.आई प्रतिबद्धता के तहत 5159.86 करोड़ रुपये का निवेश हो चुका था। जबकि नेपाल में दुनिया के बाकी देशों से कुल मिलाकर 13178.15 करोड़ रुपये का निवेश प्रस्ताव था।

जल संसाधन और ऊर्जा सहयोग

भारत सरकार ने सक्रिय रूप से लाल बाकेया, बागमती और कमला नदी पर निर्माण के लिए भारी सहायता प्रदान की है। नेपाल को इस मामल में कुल 4.5 अरब रुपये की सहायता प्रदान की गई है। 132 केवी, 33 केवी, 11 केवी के तमाम ट्रांसमिशन एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और बार्डर क्षेत्र में विद्युत का आदान–प्रदान कर रहे हैं। वे विद्युत व्यापार में जुड़े हुए हैं। धाबेलकल (नेपाल) और मुजफ्फरपुर (भारत) क्रास बार्डर ट्रांसमिशन लाइन का उद्घाटन 2016 में हुआ था। उम्मीद की जाती है कि 2019 तक इसका संचालन शुरू हो जाएगा। फिलहाल .80 मेगावाट बिजली की आपूर्ति नेपाल को हो रही है। भारत रेल, रोड, स्वास्थ्य और शिक्षा के अलावा अन्य कई क्षेत्रों में भी नेपाल को सहायता प्रदान कर रहा है।

गोरखा सैनिक

यह जानना भी दिलचस्प होगा कि हमारे देश में गोरखा रेजीमेंट है, जिसमें नेपाल के तमाम पहाड़ी क्षेत्रों के युवाओं को भी शामिल किया जाता है।

नेपाल और भूटान के साथ बहुपक्षीय कार्यक्रम

यात्री वैयक्तिक तथा मालवाहक गाड़ियों के यातायात विनियमन के लिए बांग्लादेश, भूटान, भारत, नेपाल (बी.बी. आई.एन) मोटरगाड़ी करार (एम.वी.ए) पर 15 जून, 2015 को थिम्पू में बांग्लादेश, भूटान, भारत तथा नेपाल के परिवहन मंत्रियों द्वारा हस्ताक्षर किए गए। बी.बी.आई.एन की संयुक्त कार्य समूह की एक बैठक जल व विद्युत पर तथा दूसरी बैठक पारगमन व कनैक्टिवटी पर 19–20 जनवरी, 2016 को ढाका में संपन्न हुई।

भारत–नेपाल क्षेत्रीय सहयोग

भारत के प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी 30 और 31 अगस्त 2018 को चौथें बिम्सटेक शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए काठमांडू गए थे। शिखर सम्मेलन से पहले 29 अगस्त 2018 को 16 वीं विदेश मंत्रियों की बैठक आयोजित की गई थी जिसमें विदेश मंत्री श्रीमती सुषमा स्वराज ने भाग लिया। प्रधानमंत्री ने द्विपक्षीय चर्चा के लिए शिखर सम्मेलन के दौरान अपने नेपाली समकक्षों से मुलाकात की।

नेपाल के उप–प्रधान मंत्री और स्वास्थ्य और जनसंख्या मंत्री, श्री उपेन्द्र यादव डब्ल्यू.एच.ओ पार्टनर्स फोरम 2018 में भाग दिल्ली में 4 और 5 दिसंबर 2018 को भारत के राजस्व सूचना निदेशालय द्वारा आयोजित 5 वीं क्षेत्रीय सीमा शुल्क प्रवर्तन बैठक में भाग लेने के लिए 11–14 दिसंबर 2018 के दौरान भारत आए। नेपाल के राजस्व अन्वेषण विभाग के महानिदेशक ने 15 से 16 जनवरी 2019 को नई दिल्ली में नागर विमानन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा आयोजित ग्लोबल एविएशन शिखर सम्मेलन में नेपाल के संस्कृति, पर्यटन और नागरिक उड्डयन मंत्री श्री रवीन्द्र प्रसाद अधिकारी भाग लेंगे।

प्रधानमंत्री मोदी और बिम्स्टेक सम्मेलन

विगत पांच सालों में नयी पड़ोसी नीति के केन्द्र में नेपाल भारतीय विदेश नीति का केन्द्र बिन्दु बना हुआ है। भारतीय प्रधानमंत्री मोदी के नेपाल की यात्रा 3–4 अगस्त, दूसरी यात्रा 25–27 नवम्बर, 2014 जिसमें 18वें सार्क सम्मेलन में उन्होंने हिस्सा लिया। इसके बाद नेपाल की यात्रा 11–12 मई, 2018 को हुई और इसके बाद 30–31 अगस्त, 2018 में जिसमें उन्होंने चौथे बिम्स्टेक सम्मेलन में हिस्सा लिया, जो काठमांडु में आयोजित किया गया था। इन चार यात्राओं के अतिरिक्त नेपाल के प्रधानमंत्री ने भी 2016 तथा 2018 में भारत की यात्रा की और इतनी बार ही उन्होंने चीन की भी यात्रा की। इन यात्राओं का उद्देश्य भारत–नेपाल के बीच विश्वास को बढ़ावा देना है जो तराई में मद्धेशिया नाकाबंदी (सितंबर 2015, फरवरी 2016) से कमजोर पड़ गया था और नेपाल इसके लिए भारत को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष ढंग से उत्तरदायी मानता था। इन सब गतिविधियों से आखिर फायदा क्या मिला? जब भारत विरोधी भावना को खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है, चीन नेपाल के अन्दर अपनी रणनीतिक उपस्थिति बनाये हुए है।

नेपाल ने भारत के ऊपर आक्षेप लगाना जारी रखा है कि वह नेपाल के आंतरिक विषयों में हस्तक्षेप कर रहा है। जून 2019 में रिपोर्ट आयी है जिसमें कहा गया है कि नेपाली विद्यालयों में मेनदारिन को अनिवार्य बना दिया गया है, चीन ने मेनदारिन अध्यापकों को वेतन देने का भी प्रस्ताव दिया हैं। कैसे नेपाल के मावोवादी 'सांस्कृतिक साम्राज्यवाद' को देखने में असफल है?

भारत–नेपाल : भविष्य की राहें

उभरते हुए लोकप्रिय राष्ट्रवाद के पीछे लोकतंत्रीकरण के साथ–साथ चीन समर्थक राजनीतिक दलों द्वारा नेपाल के अन्दर भारत विदेशी भावना को बढ़ावा देना भी महत्वपूर्ण कारण है। भारतीय मूल के मद्धेशिया समुदाय नेपाल की जनसंख्या का 35 प्रतिशत है। ये लोग हिंसक प्रदर्शन से अपने लिए अलग मद्धेशिया राज्य की मांग करते है जो नेपाल के तराई क्षेत्र में हैं। नवम्बर, 2014 में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की द्वितीय यात्रा के दौरान बताया गया कि नये संविधान में सभी नेपालियों की आकांक्षाओं को सम्मिलित किया गया है, उन लोगों को भी जो पर्वतीय समुदाय के अभियान समुदाय से जुड़े हैं और नेपाली राजनीतिक दलों के साथ नीचे उतरना नहीं चाहते।

सितम्बर, 2015 को नेपाली संविधान मद्धेशिया के अलग राज्य की मांग को स्वीकार नहीं करता। जिसके परिणामस्वरूप मद्धेशियाओं के पांच माह लम्बी नाकाबंदी, सितम्बर 2015 से फरवरी 2016 तक की थी जिससे नेपाल के लोगों को अत्यंत कठिनाई हुयी क्योंकि नेपाल को आवश्यक सामानों की आपूर्ति नहीं हो पा रही थी। हालांकि भारत ने आधिकारिक रूप से इस नाकेबंदी से अपने को अलग किया था लेकिन नेपाल के अन्दर जो संदेश जा रहा था उसमें यह माना जा रहा था इसमें भारत की सहमति है। इससे आंतरिक विषयों में हस्तक्षेप करने के आरोप को बढ़ावा तो मिला ही, दोनों देशों में आपसी विश्वास भी कमजोर पड़ा।

11 अक्तूबर, 2015 को प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने नवनिर्वाचित प्रधानमंत्री श्री के. पी. एस. ओली को बधाई दी। कार्यभार ग्रहण करने के एक सप्ताह के अंदर ही नेपाल के उप प्रधानमंत्री व विदेश मंत्री श्री कमल थापा ने 17–19 अक्तूबर, 2015 तक भारत का दौरा किया। अगस्त, 2014 में प्रधानमंत्री के नेपाल दौरे के दौरान घोषित ''भारत नेपाल मैत्री शिक्षा कार्यक्रम'' के तहत नेपाल तथा भारत में अध्ययन करने के लिए 2015 में लगभग 3000 नेपाली छात्रों को छात्रवृत्तियां प्रदान की गई थीं। नेपाल के उप प्रधानमंत्री व विदेश मंत्री श्री कमल थापा ने 2–3 दिसंबर, 2015 तक भारत का पुनः दौरा किया। उन्होंने नेपाल सरकार द्वारा मधेसी मुद्दों को निपटाने के लिए उठाए जा रहे कदमों के बारे में विदेश मंत्री को अवगत कराया। मुख्य मधेसी नेता श्री महंता ठाकुर, श्री उपेन्द्र यादव, श्री राजेन्द्र महतो और श्री महेन्द्र राय यादव ने 5–9 दिसंबर, 2015 तक भारत का दौरा किया। इस प्रतिननिधिमंडल ने विदेश मंत्री तथा अन्य राजनीतकि नेताओं से मुलाकात की।

फरवरी 2016 में नेपाल के प्रधानमंत्री भारत की यात्रा पर आये। नेपाल के प्रधानमंत्री श्री के. पी. शर्मा ओली ने कार्यभार ग्रहण करने के पश्चात अपने प्रथम विदेश दौरे में, 19–24 फरवरी, 2016 तक भारत का दौरा किया। इससे पूर्व प्रारंभिक दौरे के रूप में नेपाल के वित्त मंत्री श्री विष्णु पौडेल ने 7–8 फरवरी, 2016 तक भारत का दौरा किया। प्रधानमंत्री ओली की भारत यात्रा के दौरान भारत–नेपाल संबंधों पर चर्चा हुई जिनमें नेपाल में विकास और साथ ही पुनर्निर्माण, ऊर्जा तथा संस्कृति जैसे क्षेत्रों में सहयोग शामिल है।

ओली ने घोषणा की कि सभी द्विपक्षियों गलतफहमियों को हल कर लिया गया है। के0पी0 शर्मा ओली जो सी0पी0एन0 (यू०एन०एल0) के उम्मीदवार तथा भारत विरोधी भावना के कारण 2017 के चुनाव में सत्ता में आये थे। ओली ने भारत की दुसरी यात्रा अप्रैल, 2018 में की और दोनों देशों ने तीन समझौतों पर हस्ताक्षर किये कृषि क्षेत्र में सहभागिता, जमीनी पानी सम्पर्क तथा भारत और काठमांडू रेलवे सम्पर्क को बढ़ाना। इन सम्पर्क समझौतों को 'पथ–तोड़' तथा 1950 के समझौते में किसी प्रकार के सुधार को ध्यानपूर्वक देखकर करने की बात की गयी और मद्धेशियों की उचित मांगों को संवैधानिक सुधार द्वारा हल करने की बात कही गयी। मई, 2019 में मोदी ने नेपाल की चौथी यात्रा की और अपनी यात्रा को प्रधान तीर्थयात्री का नाम दिया न कि प्रधानमंत्री की यात्रा। मोदी और ओली ने एक साथ रामायण सर्किट का उद्घाटन किया, अयोध्या राम का जन्मस्थान व जनकपुर के बीच सीधें बस सेवा की शुरूआत की। इस यात्रा का उद्देश्य साझा संस्कृति तथा धर्म के सम्बन्धों से दोनों देशों के लोगों को गहरे रूप में जोड़ना था। संक्षिप्त संयुक्त बयान में नेपाल के अन्दर जो भारतीय प्रोजेक्ट लागू नहीं हो पाए हैं, उन्हें 'प्रमुख विषय' मानकर, जो व्यापार, ट्रांजिट, नदियों तथा अन्य मामलों से संबंधित है, को हल करने पर जोर दिया गया। लेकिन सम्बन्धों को पुनः स्थापित करने के लिए दोनों देशों को समानता तथा परस्पर विश्वास की डोर के साथ आगे बढ़ना होगा।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. विजय, अनंत और द्विवेदी, शिवानंद – परिवर्तन की ओर, पब्लिकेशन–प्रभात प्रकाशन 4/19 आसफ अली रोड़, नई दिल्ली, संस्करण, 2017
2. चतुर्वेदी, डॉ0 मनोज, चतुर्वेदी, डॉ0 प्रेरणा – नरेन्द्र मोदी का सर्वोदय दर्शन, पब्लिकेशन–गोपाल पब्लिशर्स एण्ड डिस्ट्रीब्यूटर्स 1/10390, तोहन पार्क, दिल्ली, संस्करण, 2016
3. वैदिक, डॉ0 वेदप्रताप – मोदी की विदेश नीति वैदिक की नजर में, पब्लिकेशन–डायमण्ड पॉकेट बुक्स प्रा0 लि0, नई दिल्ली, संस्करण, 2017
4. बघेल, बी0 एस0, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की विदेश नीति, कैटर पिल्लर पब्लिशर्स कश्मीरी गेट, दिल्ली, संस्करण–2017
5. मकवाणा, किशेर, कॉमन मैन, नरेन्द्र मोदी, प्रभात प्रकाशन 4/19 आसफ अली रोड, नई दिल्ली, संस्करण–2016
6. वर्ल्ड फोकस – भारत और पड़ोसी देश (विशेषांक), वर्ष–5, अंक–43, संस्करण–अक्टूबर, 2015
7. वर्ल्ड फोकस – भारत और पड़ोसी देश (विशेषांक), वर्ष–6, अंक–56, संस्करण–नवंबर, 2016
8. वर्ल्ड फोकस – भारत और पड़ोसी देश (विशेषांक), वर्ष–8, अंक–73, संस्करण–अप्रैल, 2018

9. वर्ल्ड फोकस – भारत और पड़ोसी उसके देश (विशेषांक), वर्ष–9, अंक–92, संस्करण– नवंबर, 2019

10. वर्ल्ड फोकस – भारत और पड़ोसी उसके देश (विशेषांक), वर्ष–11, अंक–97, संस्करण– अप्रैल, 2020

11. विदेश मंत्रालय, वार्षिक रिपोर्ट, 2018-19

12. विदेश मंत्रालय, वार्षिक रिपोर्ट, 2019-20

Websites :

13. Sood, Rrakesh (2018) A Reset in India-Nepal Relations East Asia Forum, 087 June 2018. Available At: https:// www.eastasiaforrum.org/2018/06/08/a-reset-in-indianepal-relations/

14. Bhattarai, K.D. (2018) Resetting India-Nepal Relations, The Diplomat, April, 2018 Available At: https:// thediplomat.com/2018/04/resetting-india-nepal-rela-tions/

15. Pant, Harsh V. (2018) Why India needs to Safeguard her ties with Nepal, Observer Research Foundation, June 27, 2018. Available At https://www.orfonline.org/ research/41945-why-india-needs-to-safeguard-its-tieswith-nepal?

16. Panda, Baijayanti, "India's Foreign Policy: Gentrify Relations with Neighbours", The Economic Times. July 13, 2018